असंतुष्टों को सख्त संदेश

एक और महत्वपूर्ण संकेत राहुल गांधी की तरफ से आया, जब पार्टी नेताओं द्वारा दोबारा पार्टी अध्यक्ष पद स्वीकार करने के औपचारिक आग्रह के जवाब में उन्होंने कहा, वह इस पर विचार करने को तैयार हैं।

मनोज शर्मा।।

कांग्रेस कार्यसमिति की महत्वपूर्ण बैठक के जरिए नेतृत्व ने न केवल पार्टी के अंदर के असंतुष्टों को सख्त संदेश दिया बल्कि उनके उठाए मुद्दों को भी संबोधित किया। बैठक में पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जिस लहजे में बात रखी, वह खास तौर पर ध्यान देने लायक था। उन्होंने साफ–साफ कहा कि वह पार्टी की पूर्णकालिक अध्यक्ष हैं और साफगोई पसंद करती हैं। इसलिए किसी को उनसे मीडिया के जरिए संवाद करने की जरूरत नहीं है। यह जी–23 के रूप में रेखांकित किए गए कपिल सिब्बल जैसे उन नेताओं को जवाब था, जो अक्सर कहते रहे हैं कि पार्टी को एक पूर्णकालिक अध्यक्ष की जरूरत है। हालांकि इसके साथ ही सोनिया ने यह भी कहा कि उन्हें अच्छी तरह अहसास है, वह एक अंतरिम अध्यक्ष हैं। इसलिए पार्टी ने 30 जून तक एक नियमित अध्यक्ष चुनने का फैसला किया था। मगर कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए चुनाव स्थगित करने पड़े। कार्यसमिति ने अगले साल अगस्त–सितंबर तक नया अध्यक्ष चुनने का भी संकेत दिया। एक और महत्वपूर्ण संकेत राहुल गांधी की तरफ से आया, जब पार्टी नेताओं द्वारा दोबारा पार्टी अध्यक्ष पद स्वीकार करने के औपचारिक आग्रह के जवाब में उन्होंने कहा, वह इस पर विचार करने को तैयार हैं।

इसका मतलब एक तो यह हुआ कि पार्टी अध्यक्ष पद के लिए जिस चुनाव की बात हो रही है वह औपचारिकता से ज्यादा कुछ नहीं होगा। अगर राहुल गांधी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हुए तो हो सकता है कोई और खड़ा ही न हो, वह निर्विरोध निर्वाचित हो जाएं। अगर कोई खड़ा हुआ तो भी लड़ाई सांकेतिक ही होगी क्योंकि राहुल का चुना जाना लगभग तय है। इसका दूसरा मतलब यह है कि पार्टी के गांधी परिवार की पकड़ से बाहर आने की जो संभावना पिछले कुछ समय से बताई जा रही थी, उसे समाप्त मान लेना चाहिए। यानी पारिवारिक वर्चस्व आदि जिन कमजोरियों के लिए कांग्रेस पार्टी जानी जाती रही है, उनसे उसके निजात पाने की अब निकट भविष्य में कोई सूरत नहीं दिख रही।

देखना होगा कि मौजूदा चुनौतियों के संदर्भ में आने वाले समय में ये उसकी ताकत साबित होती हैं या कमजोरी। लेकिन जहां तक पार्टी की रोज–रोज की बयानबाजी जैसे सिरदर्द की बात है तो जी–23 नेताओं का मुंह बंद करने की कोशिशों के बावजूद पार्टी की यह परेशानी दूर नहीं होने वाली। इसका ताजा उदाहरण पंजाब से आया, जहां दो दिन पहले पार्टी नेतृत्व पर पूरा विश्वास जताने वाले सिद्धू ने फिर सोनिया गांधी को लंबा पत्र लिखते हुए ऐसे 13 मुद्दे गिनाए, जिन पर उनके मुताबिक राज्य सरकार को अपने वादे पूरे करने चाहिए।

दान

अशोक वोहरा।

अंत में कंजूस को राज दरबार में पूरा हाल सुनाने के लिए राजा के सामने पेश किया गया। कंजूस ने बीती रात, सांप व बादाम के छिलकों के संघर्ष की पूरी कहानी कह सुनाई और कहा, "महाराज, मरने के बाद सबसे ज्यादा दान ही काम आता है, अतः दान करना ही सब धर्मों से श्रेष्ठ है।" किसी नगर में एक बूढ़ा चोर रहता था। सोलह वर्षीय उसका एक लड़का भी था। चोर जब ज्यादा बूढ़ा हो गया तो अपने बेटे को चोरी की विद्या सिखाने लगा। कुछ ही दिनों में वह लड़का चोरी विद्या में प्रवीण हो गया। दोनों बाप बेटा आराम से जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन चोर ने अपने बेटे से कहा, "देखो बेटा, साधु–संतों की बात कभी नहीं सुननी चाहिए। अगर कहीं कोई महात्मा उपदेश देता हो तो अपने कानों में उंगली डालकर वहां से भाग जाना, समझे। "हां बापू, समझ गया।"

संपादकीय

चीन के प्रयोग

चीन की तर्ज पर आबादी घटाने या बढ़ाने को लेकर सरकारी नीतियों का सवाल है तो यह समझना चाहिए कि दोनों ही गलत हैं। सरकार का काम यह सोचना है ही नहीं कि कौन कितने बच्चे पैदा करे। यह लोग तय करेंगे। सरकार का काम यह देखना है कि जो आबादी है उसके लिए स्वास्थ्य और शिक्षा का अच्छा इंतजाम है या नहीं। दूसरे शब्दों में सरकार यह तय नहीं कर सकती कि कौन कितने बच्चे पैदा करे, लेकिन अच्छी शिक्षा का इंतजाम करके लोगों को इस स्थिति में ला सकती है कि वे सभी पहलुओं पर विचार करते हुए सही फैसला कर सकें। सर्वे रिपोर्ट का एक पॉजिटिव पहलू यह है कि सेक्स रेशियो बदल रहा है। इन आंकड़ों के मुताबिक प्रति हजार पुरुषों पर 1020 महिलाएं पाई गई हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में अंतर और ज्यादा है। पहली नजर में यह निश्चित रूप से स्वागत योग्य डिवेलपमेंट कहा जाएगा। लेकिन थोड़ी बारीकी में जाएं तो तस्वीर पूरी तरह साफ होने के लिए कई और तरह के आंकड़ों की जरूरत है जो अभी सामने नहीं आए हैं। मसलन, ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की ज्यादा संख्या का सच समझने के लिए हमें पलायन से जुड़े आंकड़ों पर भी नजर डालनी होगी। काम की तलाश में गांव छोड़कर शहर जाने वालों में कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं, यह साफ होना जरूरी है। दूसरी बात यह कि छह साल से कम उम्र के बच्चों में अभी भी लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले कम है, जो चिंता की बात होनी चाहिए। वैसे चीन समेत कई ऐसे देश हैं जहां लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से टैक्स में छूट और लंबी मैटर्निटी लीव जैसे।

जनगणना में देश की पूरी आबादी शामिल रहती है जबकि एनएफएचएस के दायरे में रिप्रॉडक्टिव उम्र के लोग ही आते हैं। इसलिए एनएफएचएस की रिपोर्ट को उतना प्रामाणिक नहीं माना जाता, जितना सेंसस के आंकड़े माने जाते हैं।

आंकड़ों की सचाई

डॉ. दीपा सिन्हा।।

नैशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (एनएफएचएस–5) की ताजा रिपोर्ट आने के बाद से यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या देश की आबादी सचमुच बढ़ने के बजाय अब घटने लगी है? दरअसल, पिछले हफ्ते आई इस रिपोर्ट के मुताबिक देश का टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 के पिछले रेट से घटकर 2.0 हो गया है। गौरतलब है कि फर्टिलिटी रेट 2.1 रहे तो माना जाता है कि आबादी कमोबेश स्थिर रहती है। चूंकि देश में राष्ट्रीय प्रजनन दर 2.0 पर आ गई है, यानी बैलेंसिंग रेट से भी नीचे चला गया है तो कुछ हलकों में ऐसी चिंता भी जताई जाने लगी है कि देश की आबादी अब बढ़ने के बजाय कहीं घटने न लगी हो।

इस बारे में समझने वाली पहली बात तो यह है कि नैशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट और जनगणना के आंकड़ों में फर्क होता है। जनगणना में देश की पूरी आबादी शामिल रहती है जबकि एनएफएचएस के दायरे में रिप्रॉडक्टिव उम्र के लोग ही आते हैं। इसलिए एनएफएचएस की रिपोर्ट को उतना प्रामाणिक नहीं माना जाता, जितना सेंसस के आंकड़े माने जाते हैं। इसके बावजूद इन आंकड़ों की सचाई में संदेह नहीं किया जा सकता। वजह यह कि ये आंकड़े ऐसी

कोई बात नहीं कह रहे, जो अप्रत्याशित हो। इससे पहले की तमाम रिपोर्टों में यह बात आती रही है कि देश में फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है। इसलिए मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि एनएफएचएस–5 के आंकड़े देश की वास्तविक स्थिति ही दिखा रहे हैं। फिर भी फर्टिलिटी रेट के 2.1 से जरा सा नीचे जाने का यह मतलब नहीं है कि देश की आबादी तत्काल प्रभाव से कम होने लगेगी। इसकी वजह यह कि भले लोग बच्चे कम पैदा करें, लेकिन रिप्रॉडक्टिव एज में लोग अभी ज्यादा हैं। इसलिए देश की जनसंख्या तुरंत कम नहीं होगी। हां, यह जरूर है कि अगर यह ट्रेंड जारी रहा तो कुछ वर्षों में पीक पर पहुंचने के बाद आबादी कम होने लगेगी। मगर यह कोई नई या अनोखी बात नहीं है। ऐसा होता है। दुनिया के अलग–अलग देशों में देखा गया है, आबादी पहले तेजी से बढ़ती है, उसके बाद इसकी रफ्तार कम होने लगती है और फिर धीरे–धीरे वह बिंदु आता है जहां से आबादी घटने लगती है।

ऐसे में आबादी बढ़ने–घटने का हिसाब लगाने से ज्यादा जरूरी यह समझना है कि अगले कुछ वर्षों में देश में ऐसी स्थिति आएगी जब युवा आबादी का प्रतिशत कम होगा और बुजुर्गों की तादाद ज्यादा होगी। यानी जिसे हम डैमोग्राफिक डिविडेंड कहते रहे हैं, वह खत्म हो जाएगा। अगर देश में काम करने वाले लोगों की संख्या कम होगी और उस पर निर्भर आबादी ज्यादा होगी, तो जाहिर है उन सबकी जरूरतें पूरी करने, उनके लिए पेंशन आदि का इंतजाम करने जैसी चुनौतियां सामने आएंगी। ये आनी ही हैं। इनसे निपटने के लिए अलग तरह की तैयारियां चाहिए। लेकिन इस ओर सोचने का काम अभी अपने यहां शुरू भी नहीं हुआ है। हमारे यहां इस मसले को अक्सर चीन के ही संदर्भ में देखा और समझा जा रहा है। यानी जैसे चीन ने पहले आबादी की तेजी से बढ़ती रफ्तार से निपटने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई और फिर कम होते फर्टिलिटी रेट के चलते ज्यादा बच्चे पैदा करने पर जोर दे रहा है।

अष्टयोग-4907

1			4	3		2
5	33	7	35		28	
		2		6		5
	32	3	38		32	
7	5			4	2	1
	33	1	31		30	4
3			6		5	

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों और के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 4906 का हल

4	3	7	5	6	1	2
5	33	3	35	1	27	7
6	1	4	7	2	5	3
3	26	2	40	7	34	6
1	3	6	7	5	2	4
2	29	1	33	4	30	5
7	4	5	2	3	6	1

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

किसी ठोस नीति पर अमल नहीं हुआ

मोहन। दिल्ली में प्रदूषण बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। ठंड की दस्तक के साथ ही वायु प्रदूषण ने अपना करिश्मा दिखाना शुरू कर दिया। वायु प्रदूषण अधिक बढ़ने से लोगों की सांसे थमने लगी हैं। यह मसला साल–दर–साल का है, लेकिन दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए किसी ठोस नीति पर अमल नहीं हुआ। सुप्रीमकोर्ट अक्सर वायु प्रदूषण को लेकर तल्ख और गंभीर टिप्पणी करती है, लेकिन बात जहां की तहां रह जाती है। दिल्ली दुनिया के 10 प्रदूषित शहरों में सबसे अधिक प्रदूषित है। मुंबई और कोलकाता भी इसमें शुमार है। लेकिन दिल्ली जैसे हालात देश के अन्य शहरों के नहीं हैं। प्रदूषण की लड़ाई को राजनीतिक रंग दे दिया गया है। दिल्ली में यमुना की गंदगी, पराली और वायु प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दे भी राजनीति के शिकार हैं। जिसकी वजह से कोई ठोसनीति नहीं बन पा रहीं है। केंद्र और न ही राज्य सरकारों के पास प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोई खाका नहीं है।